

सरकारी दवा खरीद में आरक्षण चाहते हैं पंजाब के फार्मा उद्यमी

बिजनेस भास्कर ► चंडीगढ़...

टैक्स फ्री पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से प्रतिस्पर्धा में पिछड़े पंजाब के फार्मास्युटिकल उद्यमी राज्य की दवा खरीद नीति में आरक्षण और फार्मा क्लस्टर की मांग कर रहे हैं। पंजाब स्माल ड्रग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसीडेंट एचआर गोयल के मुताबिक पंजाब सरकार को स्माल स्केल इंडस्ट्री को टैक्स फ्री पड़ोसी राज्यों से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। हिमाचल प्रदेश अपने स्थानीय दवा निर्माताओं को सरकारी खरीद में 15 फीसदी आरक्षण देता है, जबकि पंजाब में ऐसा नहीं है। यदि पंजाब अपने सरकारी अस्पतालों और मुफ्त दवा वितरण के लिए स्थानीय ड्रग निर्माताओं से दवा खरीद सुनिश्चित करे तो बंद होने के कगार पर खड़ी ड्रग इंडस्ट्री बच सकती है। सरकार ने सरकारी खरीद के लिए पांच

मात्र 50 से 60 फार्मा इकाइयां हैं कार्यरत

पंजाब में फार्मास्युटिकल मैनुफैक्चरिंग के तकरीबन 300 लाइसेंस हैं, जिसमें से वर्तमान में केवल 50-60 इकाइयों में उत्पादन हो रहा है। इनमें हो रहे उत्पादन में से 15% निर्यात हो रहा है। इनमें 6,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बहुत सी इकाइयां हिमाचल के बड़ी, बरोटीवाला और टालीवाल में शिफ्ट हो गईं और बहुत सी इकाइयों ने उत्पादन बंद कर बड़ी से सस्ती दवाओं की ट्रेडिंग अपने ब्रांड से शुरू कर दी।

करोड़ सालाना टर्नओवर की शर्त लगा रखी है, जो एक स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिए संभव नहीं है। सरकार को फार्मा क्लस्टर के जरिए इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास इंफ्रा उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि हम निर्यात बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बन

सकें। पंजाब स्माल ड्रग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीप सिंह के मुताबिक पंजाब में दवा पर तो चार फीसदी वैट है लेकिन डाइट सप्लीमेंट्स पर वैट की दर 13.75 फीसदी है। पंजाब सरकार को डाइट सप्लीमेंट्स पर वैट की दर दवा के समान ही करनी चाहिए, ताकि हम इसमें भी अन्य राज्यों व बड़ी दवा कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। फार्मा क्लस्टर स्थापित कर हमें विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना चाहिए। लुधियाना ड्रग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैपल सरीन के मुताबिक राज्य सरकार को नए फोकल प्वाइंट विकसित कर रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध करानी चाहिए। बिजली की दरें पड़ोसी राज्यों के समान होनी चाहिए। सरकार को अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए विशेष रियायतें जैसे फ्रेट सब्सिडी, सस्ता कर्ज और सरकारी अस्पतालों में खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए।